दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्यकरण पर नीतिगत निर्णय

5533. श्रीमती सुषमा स्वराज :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के निराशाजनक कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अनेकों बार नीतिगत निर्णय किये गये है,

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त संस्थान के संबंध में लिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान वे निर्णय किस-किस तारीख को लिये गये,

(ग) मार्च, 1994 तक क्रियान्वित किये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या यह भी सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थान के कार्यकरण में सुधार के लिए अब तक किये गये निर्णयों के कार्यान्वयन में हुए विलंब के कारण दिल्ली के आम बिजली उपभोक्ताओं की कठिनाइयां बढ़ रही है, और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कार्यान्वयन में किये गये विलंब के क्या कारण है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) डेसू के कार्यकरण को सुधारने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निम्नलिखित मुख्य नीतिपरक निर्णय लिए गए है :—

(1) दिल्ली में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र में बवाना में 400/450 मे० वा० गैस टरबाईन परियोजना की प्रतिष्ठापना (दिसम्बर, 1991)।

(2) दिल्ली नगर निगम से डेसू को विलग करने के लिए तथा डेसू को विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के तहत विद्युत बोर्ड में परिवर्तित करने के लिए (जुलाई, 1992)।

(3) दिल्ली में विद्युत वितरण का निजीकरण (मार्च, 1993)।

(4) डेसू की हानियों में कमी लाने के लिए विद्युत टैरिफ का संशोधन (1 अक्तूबर, 1993)।

(ग) से (ङ) बवाना परियोजना की स्थापना के लिए निजी पार्टियों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन डेसू द्वारा किया जा रहा है ताकि वांछित रूप से समुचित प्रस्ताव का चयन किया जा सके। दिल्ली नगर निगम की पुन:संरचना जिसमें डेसू को दिल्ली नगर निगम से विलग करना भी सम्मिलित है, के लिए आवश्यक विधेयक, 1993 में पारित किया गया है। दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में विद्युत वितरण निजी क्षेत्र को सौंपने के लिए निजी पार्टियों से प्रस्ताव भी मांगे है तथा विस्तृत बोलियां आमंत्रित करने के लिए प्रस्तावों की छटाई की जा रही है। अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने की दृष्टि से डेसू ने 1-10-1993 से अपनी टैरिफ में संशोधन किया है। दिल्ली में विद्युत वितरण के निजीकरण के निर्णय को दृष्टि में रखते हुए तथा डेसू को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केन्द्रीय विद्युत यूटीलिटीज पर बड़ी मात्रा में निर्भरता को देखते हुए सरकार डेसू की पुन:संरचना की व्यवहार्यता पर विचार कर रही है ताकि राजधानी में विद्युत आपूर्ति प्रणाली के लिए एक उपयुक्त तथा कुशल प्रबन्ध सुदृढ़ करवाया जा सके। डेसू के पुनर्गठन पर किसी तरह का निर्णय लेते हुए आम उपभोक्ता के हितों के प्रति पर्याप्त सावधानी बरती जायेगी।

Supply of High Voltage Direct Current Units

5534. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Power Grid Corporation of India recently finalised a contract with a French Company for supply of high voltage direct current units in one of the first direct tie-ups with foreign investors;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether such units are available with BHEL if so, what are the reasons for importing them from France?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) Powergrid Corporation of India has recently signed a contract for Chandrapur HVDC back-to-back (2X500 MW) project with the Consortium of British and French Companies. International competitive bids with financial package were invited for the Project. BHEL in collaboration with M/s. ABB Sweden also participated in the bidding. The Consortium's bid was the lowest

Outlay for Power Generation in Gujarat

5535. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(g) whether Government have enhanced the total outlay for power sector for Gujarat for 1994-95;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the schemes initiated for improving the power sector in Gujarat during the above period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P.V RANGAYYA NAIDU): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise in view of (a) above.

कहलगांव ताप विद्युत केन्द्र को स्थानान्तरित किया जाना

5536. श्री जनार्दन यादव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कहलगांव स्थित ताप विद्युत केन्द्र की प्रस्तावित थ्रिड को बांका से बिहार शरीफ में स्थानांतरित कर दिया गया है,

(ख) क्या निकट भविष्य में इसे पुन: बांका स्थानांतरित किये जाने का कोई प्रस्ताव है,

(ग) यदि हां, तो कब तक, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कहलगांव ताप विद्युत केन्द्र से विस्थापित व्यक्ति

5537. श्री जनार्दन यादव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कहलगांव स्थित ताप विद्युत केन्द्र के कारण कितने लोग विस्थापित हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने लोगों का पुनर्वास किया गया है; और

(ग) अभी बचे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें पुनर्वासित करने के बारे में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०) के बिहार में कहलगांव स्थित ताप विद्युत केन्द्र के कारण कुल 131 व्यक्ति विस्थापित हुए हैं।

(ख) और (ग) इन सभी व्यक्तियों को प्लाट आवंटित कर दिए गए हैं और इनका पुनर्वास कर दिया गया है। इनमें से 21 व्यक्तियों को पहले ही कहलगांव परियोजना में रोजगार प्रदान किया जा चुका है। शेष विस्थापित व्यक्तियों को सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि लाभप्रद रोजगार के लिए ठेका दिये जाने के लिए उनके ठेके पर विचार किया जा सके इसके अलावा, विभिन्न, प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है ताकि स्वरोजगार स्कीम के लिए वे अपने को तैयार कर सकें।

Strategies for Energy Conservation

5538. SHRI M.A BABY: Will the Minister of POWER be pleased to state;

(a) the details of the short term and long term strategies and innovations evolved by the Ministry with regard to energy conservation in different Public Sector as well as private sector units during the last three years together with the results achieved through these projects; and

(b) the details of perspective planning for energy conservation till year 2000 together with the projected targets and money allocated for Research and Development in this area?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) With a view to promoting energy conservation in different public sector as well as private sector units, the Minis-try of Power is encouraging the promotion of energy audits, setting up of demonstration projects, supporting training, awareness building & publicity campaigns and extending fiscal and financial benefits for energy saving equipments.

(b) An Action Plan to implement the national Energy Efficiency Programme in the 8th Plan prepared by the Planning Commission has been drawn up. It envisages savings equivalent to 5000 MW to installed generating